



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 142/18

निर्णय दिनांक 18.05.2018

1. कानाराम पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांत

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 09-07-2010
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़

उपस्थित:-

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांत
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांत ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन के आदेश दिनांक 09-07-2010 जिसके द्वारा अपीलांत का विशेष आवंटन आवेदन निरस्त किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ. गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांत ने विशेष आवंटन के तहत चक 5 एमआरएम के मुरब्बा

नम्बर 212/52 की भूमि आवंटन किये जाने हेतु श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 09-07-2010 को अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांट का भूमिहीन आवंटन आवेदन को निरस्त कर दिया जो कानून एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट के धारण में 4 बीघा भूमि कमाण्ड से अधिक भूमि आती है व सबूत अपूर्ण है। जबकि आवंटन नियमों में वरियता अथवा पात्रता निर्धारण करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश आवंटन नियमों के विपरीत होने से व कानून एवं विधि के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है, सद्भावी काश्तकार है व बीकानरे, राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया है जो कानून व विधि के विरुद्ध है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09-07-2010 के विरुद्ध अपील दिनांक 24-01-18 को पेश की है। जो करीब 08 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही 4 बीघा भूमि अधिक होने के कारण वरियता से बाहर है अतः आवेदन खारिज किया जाता है। अतः अपीलांट का आवंटन खारिज किया है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक 28-02-2008 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात् भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 09-07-2010 को अपीलांट का प्रार्थना इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट के धारण में 4 बीघा भूमि कमाण्ड से अधिक होने व सबूत अपूर्ण होने से वरियता से बाहर होने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है।

(2) हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 5 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 184/12 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थी के धारण में भूमि 4 बीघा कमाण्ड से अधिक होने के कारण व सबूत अपूर्ण होने से वरियता से बाहर मानते हुए अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन प्रार्थना व अन्य आवेदकों के प्रार्थना पत्र की जाँच के उपरान्त पाया गया कि अपीलांट द्वारा जो मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है वह स्वयं का नहीं होने व अपीलांट के धारण में पूर्व में ही अधिक निहित है व इसी आधार पर अदात मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र पूर्व में अधिक भूमि धारण में होने व सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है।

(4) चूंकि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही अधिक भूमि होने से अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र आवंटन नियमों के विपरीत होने से व पर्याप्त सबूतों के अभाव में, अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत रूप से खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 09-07-2010 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर